



संक्षिप्त समाचार

कोरोनाकाल में ठप्प पड़ी प्रयोगात्मक विषयों की पढ़ाई संवाददाता देहरादून। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों ने थ्योरी की पढ़ाई का तोड़ ऑनलाइन से निकाल दिया है, लेकिन प्रयोगात्मक विषयों की पढ़ाई ठप है। क्योंकि बिना प्रयोगशाला में प्रेक्टिकल किए प्रयोगात्मक विषयों की पढ़ाई अधूरी है। अकेले प्रदेश के 18 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 70 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के दाखिले हैं। जिनके स्नातक व स्नाकोत्तर के कई विषयों में प्रयोगात्मक कक्षाएं जरूरी हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले करीब आठ महीने से प्रदेश के विवि व कॉलेज परिसर बंद हैं।

वन महकमे की भी सांस में सांस आई

संवाददाता देहरादून। लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव ने नेमत बरसाई तो वन महकमे की भी सांस में सांस आई है। असल में अक्टूबर से बारिश न होने की वजह से राज्य में सर्दियों में जंगल सुलगने लगे थे। आकड़ों पर गौर करें तो एक अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आग की 154 घटनाओं में 210 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा। इसमें 1600 पेड़ों को भी क्षति पहुंची है। आग की निरंतर बढ़ती घटनाओं ने महकमे की बेचोनी बढ़ा दी थी और उसकी नजरें आसमान पर टिकी हुई थीं। आखिरकार इंद्रदेव ने कृपा बरसाई और वर्षा-बर्फबारी होने से जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने में मदद मिली। वन क्षेत्रों में नमी घटने का संकट भी दूर हो गया। बावजूद इसके खतरा अभी टला नहीं है।

प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की सुंदरता पर गंदगी का ग्रहण संवाददाता देहरादून। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नागटिब्बा विकास समिति और वन विभाग में तालमेल का अभाव होने से इस पर्यटक स्थल की सुंदरता को कायम रखने में परेशानी हो रही है। यहां पर बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक ट्रैकर आते हैं लेकिन उनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। यहां पर पर्यटकों का मनमाने ढंग से आवागमन होता है जिससे यहां के पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। वहीं इस पर्यटक स्थल में घूमने के लिए शुल्क नहीं लिए जाने से राजस्व की भी हानि हो रही है।

उत्तराखंड में कहां गया भिक्षावृत्ति पर रोक का कानून संवाददाता देहरादून। प्रदेश में लगभग सवा तीन साल पहले भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की। जोर-शोर से प्रचारित किया गया कि उत्तराखंड उन 20 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है। कानून तो लागू हो गया, लेकिन प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर रोक नहीं लग पाई।

मुख्यमंत्री ने किया ऋषिकेश में जानकी सेतु का लोकार्पण

घोषणा

■ ऋषिकेश में शीघ्र तैयार होगा अभिनव कला युक्त बजरंग ग्लास पुल

संवाददाता

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने तीर्थनगरी में मुनी की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित जानकी सेतु जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में बजरंग सेतु के निर्माण की घोषणा भी की। वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने मुनी की रेती और स्वर्गाश्रम के बीच जानकी सेतु के निर्माण की घोषणा की थी वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था, लेकिन तमाम अड़चनों के चलते इस पुल का समय पर निर्माण नहीं हो पाया। करीब 49 करोड़ रुपए की लागत से बने 346 मीटर लम्बे इस थी-लेन (जानकी पुल) का शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद



अग्रवाल, कबीना मंत्री सुबोध उनियाल, यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी नगर पालिका मुनिकीरेती के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन तीन वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश भर में ढाई सौ थी-लेन (जानकी पुल) का निर्माण किया है। इनमें बहुप्रतीक्षित डोबरा चांटी पुल और जानकी सेतु भी शामिल

पुल बनाने की भी घोषणा की। कई परिवारों को रोजगार मिलेगा नरेन्द्र नगर के विधायक और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जानकी सेतु सिर्फ आवागमन के लिए ही महत्व नहीं रखेगा, बल्कि इससे भविष्य में कई परिवारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इको टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के जरिए उत्तराखंड में बनाई जा रही ऑल वेदर रोड विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। यमकेश्वर विधानसभा की विधायक रितु खंडूड़ी ने कहा कि यह लोहे और लोहे की रस्सियों से बना पुल नहीं, बल्कि विश्वास आशा और स्वप्न को यथार्थ में बदलने का प्रतीक है। यह निर्माण प्रदेश में सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नगर पालिका मुनिकीरेती के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने जानकी सेतु के लोकार्पण को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री से पूर्णानंद रामझूला पुल का भार होगा कम मुनिकीरेती-स्वर्गाश्रम के बीच

भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम

सीएम रावत ने कहा, हमने प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है। भ्रष्टाचार के मामले में हमने कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। जब तक हमारी सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में 37 लाख महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही हैं। जल्द ही हम महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार देने जा रहे हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश के विकास में सहभागी बनेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में लौटे तीन लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं युवाओं को इसका लाभ लेना चाहिए।

वर्तमान में आवाजाही के लिए रामझूला पुल पर ही पूरा दारोमदार है, लेकिन जानकी सेतु के खुलने के बाद रामझूला पुल का भार कम हो जाएगा। रामझूला पुल पर आम दिनों में तो भीड़ रहती ही है, कुंभ और कांवड़ मेले जैसे आयोजनों के दौरान इस पुल पर भारी दबाव बढ़ जाता है।

59 सीटों पर हार की जिम्मेदारी मेरी: रावत

निशाना

■ हरीश रावत ने पार्टी में अपने विरोधियों पर निशाना साधा

देहरादून। संवाददाता

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने थराली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराने को लेकर फिर पार्टी में अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी जनसभा की वजह से पार्टी को हार मिली तो फिर उन्हें राज्य में 59 सीटों की चुनावी हार के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इस नई खोज के लिए वह कांग्रेसजनों विशेष रूप से चमोली के कांग्रेसजनों



को धन्यवाद देते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस के दिग्गजों में अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह इन दिनों गढ़वाल मंडल के दौरे पर हैं। इस दौरान

उनके पार्टी से रूठे व्यक्तियों की वापसी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन पर हमला बोला था। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग में प्रीतम की जनसभा में उठे एक मुद्दे को लेकर फिर हरीश रावत मुखर हो गए। वहीं,

ये भी बताया जा रहा है कि उक्त जनसभा में किसी का नाम लिए बगैर ही इशारों में चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी की हार के लिए हरीश रावत की बड़ी जनसभा को जिम्मेदार ठहराया गया। हरीश रावत ने इसे गंभीरता से लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने संगठन में एक वरिष्ठ नेता को अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि घाट में उनकी जनसभा को हार का कारण बताए जाने की नई जानकारी कर्णप्रयाग से सामने आई है। रावत की प्रतिक्रिया को आने वाले वक्त में पार्टी के भीतर सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है।

2022 तक ऊत्तराखण्ड के सभी आवासहीन को आवास उपलब्ध कराया जाएगा

संवाददाता देहरादून। 2022 तक ऊत्तराखण्ड के सभी आवासहीन को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग प्रदेश के 84726 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करेगा। यह जानकारी शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा ली गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग-बैठक में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड प्रदेश में अभी तक कुल 12662 लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति प्रदान करके लाभान्वित किया गया। इनमें से 539 भूमिहीन लाभार्थियों को पट्टे पर भूमि देकर भी लाभान्वित किया गया। इन लाभार्थियों को कनवर्जन्स योजना के तहत मनरेगा, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल सुविधा का भी लाभ दिया गया।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices
All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Read News Watch News Channel

Scan This Code

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रदीप चौधरी द्वारा एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराधर,देहरादून से मुद्रित व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित। संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय: शिवम मार्केट, द्वितीय तल दर्शनलाल चौक, देहरादून। फ़ैक्स नं०- 0135-2650558 (M) 9319700701 pagethreedaily@gmail.com आर.एन.आई.नं० UTTHIN\2005\15735 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।